मेरला रमन्ना

बनाम

नल्लापाराजू और अन्य

[भगवती, वेंकटराम अय्यर और बी.पी. सिन्हा जेजे.]

न्यायालय, डिक्री-संधारणीयता-डिक्री के अत्यधिक निष्पादन में किये गये विक्रय को अपास्त करने में वाद में-न्यायालय की शक्ति-संधारणीयता-वाद यदि एक निष्पादन आवेदन के रूप में माना जा सकता है-सीमा-न्यायालय का अंतर्निहित क्षेत्राधिकार जिसके अधिकार क्षेत्र में डिक्री का विषय-वस्तु स्थानांतरित किया गया है-प्रारंभिक चरण में आपत्ति उठाने में विफलता-सिविल प्रक्रिया की छूट-संहिता-(1908 का अधिनियम V), धारा 47-भारतीय परिसीमा अधिनियम (1908 का IX), अनुच्छेद 165, 166, 181।

अपीलकर्ता ए द्वारा निष्पादित दिनांक 14-12-1911 के बंधक का समनुदेशिती था, जिसमें बंधककर्ता की भूमि और 19-7-1909 को उसके पक्ष में उत्तरदाताओं द्वारा निष्पादित बंधक भी शामिल था। अपीलकर्ता ने बंधक पर देय राशि की वसूली के लिए दिनांक 14-12-1911 को काकीनाडा के अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा दायर किया और बंधकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय के लिए प्रार्थना की। उत्तरदाताओं को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। मुकदमे का एक पक्षीय फैसला सुनाया गया था, और डिक्री के निष्पादन में, उत्तरदाताओं की संपत्तियों को, 19-7-1909 को ए के पास गिरवी रख दिया गया था, जो कि डिक्री धारक द्वारा खरीदी गई थी। इसके बाद प्रतिवादियों ने पूर्वी गोदावरी के जिला न्यायालय में वर्तमान मुकदमा दायर किया, जिसके पास उस समय मुकदमे में संपत्तियों पर अधिकार क्षेत्र था, यह घोषणा करने के लिए कि अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त डिक्री धोखाधड़ीपूर्ण और निष्क्रिय थी और उनके हक को प्रभावित नहीं कर सकती थी। वादपत्र में बाद में

संशोधन किया गया और एक प्रार्थना में कहा गया कि संपत्तियों का विभाजन किया जा सकता है और उत्तरदाताओं को उनके हिस्से पर अलग कब्ज़ा दिया जा सकता है। विचारण न्यायाधीश ने मुकदमा खारिज कर दिया और अपील में जिला न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले की पुष्टि की। उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील में पहली बार यह तर्क दिया गया कि विचाराधीन डिक्री ने बंधक संपत्तियों की बिक्री का निर्देश नहीं दिया, बल्कि बंधक विलेख दिनांक 19-7-1909 के तहत बंधक के अधिकारों की बिक्री का निर्देश दिया। संपत्तियों की बिक्री शून्य थी। उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय से यह निर्धारित करने को कहा कि क्या बेचा गया था। जिला न्यायालय ने पाया कि डिक्री में वास्तव में गिरवीदार के अधिकारों की बिक्री का निर्देश दिया था, न कि गिरवी रखी गई संपत्तियों का और अत्यधिक निष्पादन हुआ था। हालाँकि, यह राय थी कि इस मुद्दे को निष्पादन न्यायालय के समक्ष उठाया जाना चाहिए था और जहाँ तक अत्यधिक निष्पादन के आधार पर राहत का दावा किया गया था, धारा 47 के तहत मुकदमा वर्जित था। उच्च न्यायालय ने इस आपत्ति पर विचार करने से इंकार कर दिया कि मुकदमा धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वर्जित था, क्योंकि इसे लिखित जवाबदावे में नहीं लिया गया था और पहली बार द्वितीय अपील में उठाया गया था और प्रतिवादी के मुकदमे का फैसला सुनाया गया था। अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय को आपत्ति पर विचार करना चाहिए था और यह मानना चाहिए था कि मुकदमा वर्जित है।

अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलकर्ता को उक्त तर्क उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय के अलावा अत्यधिक निष्पादन से संबंधित मुद्दा कभी भी विशेष रूप से नहीं उठाया गया था और वादपत्र में आरोप अस्पष्ट और अविनिर्दिष्ट थे। यह विधि का एक विशुद्ध प्रश्न है जिसके लिए तथ्यों की आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है और जिला न्यायालय के समक्ष पक्षों द्वारा इसे समझा और बहस की गई।

यह अच्छी तरह से तय हो गया था कि यह सवाल कि निष्पादन विक्रय डिक्री से अधिक था और इसलिए यह अपेक्षित नहीं था कि पक्षकारों के मध्य निष्पादन न्यायालय के समक्ष धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन एक आवेदन द्वारा उठाया जा सकता है, न कि एक पृथक वाद द्वारा।

जे. मैरेट बनाम. मो. के. शिराज़ी एंड संस (ए.आई.आर. 1930 पी. सी. 86), वेंकटचलपति अय्येन बनाम पेरुमल अयेन ([1912] एम.डब्ल्यू.एन. 44), बीरू महता बनाम श्यामा चरण खवास ([1895] आई एल.आर. 22 कैल. 483), अब्दुल करीम बनाम इलमुन्निसा बीबी ([1916] आई.एल.आर. 38 इलाहाबाद 339) और लक्ष्मीनारायण बनाम लादुराम ([1931] ए.आई.आर. 1932 मुम्बई 96), अनुमोदित।

हालाँकि, अदालत के पास किसी दावे में वाद पत्र को परिसीमा या अधिकार क्षेत्र के अधीन धारा 47 के तहत आवेदन के रूप में विचार करने की शक्ति थी।

यह कि आवेदन अनुच्छेद 165 के तहत वर्जित नहीं था, क्योंकि यह केवल निर्णित-ऋणी के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जे के पुनर्स्थापन के लिए आवेदनों पर लागू होता था और वर्तमान मामले में ऐसा कोई आवेदन नहीं था।

वाचाली रोहिणी वि. कोम्बी अलियासन ([1919] आई.एल.आर. 42 मद्रास 753), रत्नम अय्यर बनाम कृष्णा डॉस वाइटल डॉस ([1897] आई.एल.आर. 21 मद्रास 494), रसूल बनाम अमीना ([1922] आई.एल.आर. 46 मुम्बाई 1031) और बहिर दास बनाम गिरीश चंद्र ([1922] एआईआर. 1923 कलकत्ता 287), अनुमोदित।

न ही अनुच्छेद 166 लागू होगा, क्योंकि उक्त अनुच्छेद वहां लागू होगा जहां विक्रय शून्यकरणीय हो और शून्य विक्रय को अपास्त कराने के लिए नहीं। भारतीय परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 181 उस मामले में लागू होगा, जहां विक्रय शून्य हो, जैसा कि वर्तमान मामले में है।

शेषगिरि राव बनाम श्रीनिवास राव ([1919] 1.एल.आर. 43 मद. 313), राजगोपालियर बनाम रामानुजर्चियार ([1923] आईएलआर. 47 मद. 288), मोनमोथानाथ घोष बनाम लछमी देवी ([1927] आईएलआर 55 कैल. 96)), निरोडे काली रॉय बनाम हरेंद्र नाथ (आईएलआर. [1938] 1 कैल. 280), और 5-85 एस.सी. भारत/59 मा वी ज्ञान बनाम माठंग थान ब्यू (एआईआर. 1937 रंग. 126), अनुमोदित।

अनुच्छेद 181 के तहत किसी आवेदन के लिए परिसीमा का प्रारंभिक बिंदु क्रेता द्वारा बेदखली की तारीख होगी, न कि शून्य बिक्री की तारीख जिसका कानून में कोई अस्तित्व नहीं था और वर्तमान मुकदमे में वादपत्र, एक आवेदन के रूप में माना जाता है, जो कि बेदखली के 3 साल के भीतर दायर किया गया था।

चेंगैरया बनाम कोल्लापुरी (ए.आई.आर. 1930 मद्रास 12), अनुमोदित। पूर्वी गोदावरी का जिला न्यायालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्तियों को वर्तमान मुकदमा शुरू होने से पहले स्थानांतरित कर दिया गया था, ने इस तरह के हस्तांतरण के कारण उन पर एक अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र हासिल कर लिया था और यदि यह उनके संदर्भ में निष्पादन के लिए एक आवेदन पर विचार करता था इस तरह की कार्यवाई एक अनियमितता से अधिक कुछ नहीं थी: क्षेत्राधिकार की धारणा और अपीलकर्ता द्वारा अधिकार क्षेत्र पर कोई आपत्ति नहीं होने पर उसे जल्द से जल्द अवसर पर माफ कर दिया गया माना जाना चाहिए और, परिणामस्वरूप, वादपत्र को धारा 47 के तहत निष्पादन आवेदन के रूप में मानने में कोई कानूनी बाधा नहीं थी।

बालाकृष्णय्या बनाम लिंगा राव (आईएलआर. [1943] मद्रास 804), लागू। प्रकरण पर विचार किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 183/1952।

जिला न्यायाधीश, पूर्वी गोदावरी की अदालत के 16 मार्च, 1945 के मूल डिक्री से द्वितीय अपील संख्या 1826, 1945 में मद्रास उच्च न्यायालय के 16 फरवरी, 1950 के फैसले और डिक्री से विशेष अनुमति द्वारा अपील। ए.एस. में राजमुंदरी 1940 के सूट नंबर 17 और ओ.एस. में उप-न्यायाधीश, राजमुंदरी की अदालत के 31 अक्टूबर, 1942 के डिक्री से उत्पन्न 1943 की संख्या 32, 1939 की संख्या 39।

अपीलकर्ता की ओर से बी. सोमैया (सह श्री के.आर. चौधरी और नेयुनित लाल)।

उत्तरदाताओं संख्या 1 से 4 के लिए के.एस. कृष्णास्वामी अयंगर, (सहश्री के.आर. कृष्णा- स्वामी)

4 नवंबर, 1955 को न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया।

न्यायाधिपति वेंकटकामा अय्यर -यह दूसरी अपील में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा एक अपील है, जिसने निचली अदालतों के समवर्ती निर्णयों को उलट दिया था, और एक डिक्री प्रदान की थी।

कला-वचेरला गांव में 503 एकड़ 18 सेंट की भूमि के एक हिस्से में से 126 एकड़ 33 सेंट और 10 एकड़ 12 सेंट की भूमि के एक हिस्से में से 126 एकड़ 33 सेंट के विभाजन और कब्जे की डिक्री तथा नंदराडा गांव में 40 एकड़ 47 सेंट की सीमा तक भूत एवं भविष्यलक्षी मध्यवर्ती लाभा सहित उत्तरदाताओं के पक्ष में पारित की गई। 543 एकड़ 65 सेंट की ये सभी भूमि 5-6-1888 को पांच सह-हिस्सेदारों द्वारा दो बिक्री विलेख, प्रदर्श पी और पी-1 के तहत खरीदी गई थी। लगभग 218 एकड़ के इन शेयरों में से एक, प्रारंभिक तिथियों पर, दो भाइयों, रंगराजू और कुमारा के पास साझा था, पहला 136 एकड़ 45 सेंट और दूसरा 81 एकड़ 45 सेंट के मालिक थे। 19-8-1908 को कुमारा ने अपनी 81 एकड़ 45 सेंट से अधिक की एक साधारण बंधक, प्रदर्श, नल्लप्पाराजू के पक्ष में 1,000/-रुपये में निष्पादित की। जिन्होंने अपने अविभाजित

भाई, अच्युतरामराजू के साथ, कलावाचेरला और नंदा-राडा में पूर्वोक्त भूमि के दो हिस्सों में हिस्सेदारी रखी। 19-7-1909 को रंगाराजू और कुमारा दोनों ने उनकी सभी 218 एकड़ जमीन पर 2,000 रुपये के लिए एक बंधक, एक्ज़िबिट ए अचुतारमाराजू के पक्ष में निष्पादित किया। 4-6-1910 को कुमारा ने फिर से अपनी 81 एकड़ 45 सेंट की जमीन को 2500/-रुपये में प्रदर्श Q-1 के द्वारा अच्युतराम-राजू के पक्ष में बंधक बना लिया। 14-12-1911 को अच्युतरामाराजू ने मेरला अगसत्या के पक्ष में प्रदर्श सी 14,000/-रुपये के लिए एक बंधक निष्पादित किया। उन संपत्तियों पर, जिन्हें उन्होंने सह-हिस्सेदार के रूप में पूर्ण स्वामित्व में रखा था और बंधक अधिकार भी जो उन्होंने तीन बंधक विलेखों प्रदर्श Q, A और Q-1 के तहत रंगाराजू और कुमारा से संबंधित संपत्तियों पर रखा था। 29-8-1920 को कुमारा ने अपनी 81 एकड़ 45 सेंट जमीन बेच दी और अच्युतरामराजू को 11,000/- रुपये में प्रदर्श जी के अनुसार उपरोक्त बंधक में शामिल कर लिया। इस प्रकार दो विलेख, प्रदर्श Q, A और Q-1 पूरी तरह से मुक्त हो गए और प्रदर्श A, कुमारा के आधे हिस्से की सीमा तक। तब स्थिति यह थी कि अच्युतारामाराजू प्रदर्श ए के तहत गिरवी रखी गई संपत्तियों में से 81 एकड़ 45 सेंट के मालिक बन गए और उनमें से आधी राशि की सीमा तक उनमें से बाकी के संबंध में एक साधारण बंधक बने रहे। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 70 के आधार पर प्रदर्श जी के तहत गिरवीदार मेरला अगस्तय्या के लाभ के लिए, जो उसके गिरवीदार के हित में सहायक है बिक्री सुनिश्चित होगी।

20-1-1924 को मेरला अगास्तया के प्रतिनिधियों ने बंधक, प्रदर्श सी में अपने हितों को वर्तमान अपीलकर्ता को सौंप दिया, जिन्होंने मूल वाद संख्या 25/1927 बंधकग्रस्त सम्पत्ति की बिक्री से देय राशि की वसूली के लिए काकीनाडा के अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में संस्थित किया। गिरवी रखने वाले अच्युतारामराजू और उनके परिवार के सदस्य उस मुकदमे में प्रतिवादी 1 से 4 थे। कुमारा को 14वें प्रतिवादी के

रूप में और रंगाराजू और उनके बेटे को प्रतिवादी 15 और 16 के रूप में शामिल किया गया था। वाद में, यह अभिवचन किया गया कि प्रदर्श सी बंधक विलेख में शामिल संपत्तियों में सह-हिस्सेदारों के रूप में पूर्ण स्वामित्व में बंधककर्ताओं की संपत्तियां शामिल थीं और प्रदर्श क्यू, ए और क्यू -1 के तहत बंधक अधिकार भी शामिल थे। तब एक यह भी अभिवचन था कि प्रतिवादी 1 से 4 ने स्वयं "पहले प्रतिवादी के बंधक ऋणों के निर्वहन के लिए" गिरवी रखी गई संपत्तियों को खरीदा था। तथ्य के रूप में, यह सही नहीं था, क्योंकि अच्युतरामाराजू द्वारा केवल कुमारा की 81 एकड़ 45 सेंट भूमि खरीदी गई थी और शेष संपत्ति रंगाराजू के पास बनी रही, और अच्युतरामाराजू प्रदर्श ए के तहत केवल उसके गिरवीदार थे। आगे यह भी अभिवचन थे कि प्रतिवादी 14 से 16 को पक्षकारों के रूप में शामिल किया गया था क्योंकि उनके पास संपत्तियों का कब्जा था और वे उन संपत्तियों के संबंध में जो प्रदर्श Q-A और Q-1 तहत गिरवी रखी गई थीं के हक के पूर्ववर्ती थे। अंत में संपत्तियों के विक्रय सामान्य अनुतोष चाहा गया।

बंधककर्ता, प्रतिवादी 1 से 4, ने वादी के साथ समझौता कर लिया, जबकि प्रतिवादी 14 से 16 एक पक्षीय रहे। 31-1-1931 को प्रतिवादी 1 से 4 के विरुद्ध समझौते के आधार पर और प्रतिवादी 14 से 16 के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से मुकदमा डिक्री किया गया था और 6-11-1932 को अंतिम डिक्री पारित की गई थी। 23-8-1934 को डिक्रीधारक ने ई.पी. संख्या 99/1934 दायर की। प्रदर्श ए में उल्लिखित संपत्तियों सहित बंधक सम्पत्ति की बिक्री के लिए प्रार्थना की गई। प्रतिवादीगण 15 और 16 ने तब हस्तक्षेप किया, और आपत्ति दर्ज की उन्हें इस आधार पर बेचा जा रहा था कि 1923 में बंधक का भुगतान कर दिया गया था और उनके खिलाफ एक पक्षीय डिक्री धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी। इस आवेदन को अधीनस्थ न्यायाधीश ने 26-8-1935 को खारिज कर दिया था और इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय, मद्रास में की गई अपील भी 1-9-1938 को खारिज कर दी गई थी। इस बीच, प्रदर्श ए के तहत गिरवी रखी गई

संपत्तियों में से 163 एकड़ 18 सेंट, जिसमें से 81 एकड़ 86 सेंट रंगाराजू की थीं, 14 और 15 अप्रैल, 1936 को बिक्री के लिए लाई गईं, और डिक्री-धारक द्वारा स्वयं खरीदी गईं। 26-6-1936 को बिक्री की पुष्टि की गई और 15-12-1936 को कब्जा ले लिया गया। लेकिन कब्ज़ा लेने से पहले 14-12-1936 को रंगाराजू और उनके बेटों ने वाद संख्या 268/1936 जिला मुंसिफ कोर्ट, राजमुंदरी में मूल वाद संख्या 25/1927 में प्राप्त डिक्री कपटपूर्ण होने तथा डिक्री धारक उसकी सम्पत्तियों के विरुद्ध निष्पादन का हकदार नहीं होने की घोषणा बाबत् प्रस्तुत किया। इस मुक़दमे की सुनवाई के लिए जिला मुंसिफ़ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति की गई और अंततः, वादपत्र को उचित अदालत में प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया गया। इसके बाद, उन्होंने 7-8-1939 को वर्तमान मुकदमा, मूल वाद संख्या 39/1939 जिला न्यायालय पूर्वी गोदावरी में मूल वाद संख्या 25/1927 में अभिप्राप्त डिक्री सम्मन की सम्यक तामील न होने तथा प्रदर्श ए द्वारा पूर्व में बंधक रखी गई 136 एकड़ 45 सेंट तक उनके हक में अप्रभावी हाेकर शून्य होने बाबत् संस्थित किया गया। मुकदमा राजमुंदरी के अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था और इसे मूल वाद संख्या 79/1940 के रूप में क्रमांकित किया गया था।

अपने लिखित बयान में, अपीलकर्ता ने इस बात से इंकार किया कि मूल वाद संख्या 25/1927 में डिक्री धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी और तर्क दिया गया कि वर्तमान मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित था। उन्होंने यह भी दलील दी कि चूंकि उन्होंने डिक्री के निष्पादन में संपत्तियां खरीदी थीं और उन पर कब्ज़ा प्राप्त कर लिया था, इसलिए जो मुकदमा केवल यह घोषणा करने के लिए था कि डिक्री शून्य और निष्पादन योग्य नहीं थी, वह चलने योग्य नहीं था। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि जबकि रंगाराजू और उनके बेटों की 81 एकड़ 86.50 सेंट भूमि 14 और 15 अप्रैल, 1936 को बेच दी गई थी, उनकी शेष संपत्तियां 54 एकड़ 58) सेंट की सीमा तक मूल वाद संख्या

268/1936 जिला मुंसिफ, राजमुंदरी की अदालत में संस्थित होने के बाद बेची गई थी। उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, वादी ने एक प्रार्थना जोड़कर वाद में संशोधन किया कि अनुसूची ए में कुल 543 एकड़ 65 सेंट में से 136 एकड़ 45 सेंट और उनसे संबंधित भूमि को विभाजित किया जा सकता है और उनको अलग कब्जे में रखा जा सकता है। राजमुंदरी के अधीनस्थ न्यायाधीश ने इस आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया कि कोई धोखाधड़ी स्थापित नहीं की गई थी, और जहां तक धोखाधड़ी के आधार पर डिक्री को रद्द करने की मांग की गई थी, तब तक मुकदमे को परिसीमा द्वारा रोक दिया गया था। वादी ने इस फैसले के खिलाफ पूर्वी गोदावरी के जिला न्यायालय में अपील की, जिसने 16 मार्च, 1945 के अपने फैसले से अधीनस्थ न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि की। वादी ने तब उच्च न्यायालय, मद्रास में दूसरी अपील संख्या 1826 को प्रस्तुत की। वहां, पहली बार इस विवाद को उठाया गया कि मूल वाद संख्या 25/1927 में डिक्री बंधक अधिकारों की बिक्री का निर्देश दिया था जो अच्युतरामाराजू के पास ए अनुसूची संपत्तियों पर था, और उस डिक्री के निष्पादन में संपत्तियों की बिक्री डिक्री द्वारा निर्देशित की गई राशि से अधिक थी और इसलिए शून्य था और वादी तदनुसार बिक्री की अनदेखी करके उन संपत्तियों पर कब्ज़ा पाने के हकदार थे। न्यायाधिपति सत्यनारायण राव, जिन्होंने अपील की सुनवाई की, ने वादी को इस प्रश्न और मुद्दे (2) (बी) को इस विवाद को कवर करने के लिए पर्याप्त रूप से उठाने वाला माना और तदनुसार जिला न्यायाधीश को प्रश्न पर एक निष्कर्ष वापस करने का निर्देश दिया। क्या संपत्तियों की बिक्री डिक्री की शर्तों के अनुसार उचित थी। पूर्वी गोदावरी के जिला न्यायाधीश, जिनके पास यह मुद्दा भेजा गया था, ने माना कि डिक्री ने प्रदर्श ए के तहत केवल अच्युतारामराजू के बंधक अधिकारों की बिक्री का निर्देश दिया था और संपत्तियों की बिक्री स्वयं डिक्री के अनुरूप नहीं थी। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि यह डिक्री के निष्पादन से संबंधित एक आपत्ति थी जिसे केवल निष्पादन न्यायालय के समक्ष ही

उठाया जा सकता था, और उस मामले के संदर्भ में एक अलग मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के तहत वर्जित था।

इस निष्कर्ष पर, दूसरी अपील न्यायाधिपति सत्यनारायण राव, के समक्ष अंतिम निपटान के लिए आई, जो जिला न्यायाधीश से सहमत थे कि संपत्तियों की बिक्री डिक्री द्वारा अधिकृत नहीं थी और इसलिए शून्य थी। लेकिन उन्होंने इस आपत्ति पर विचार करने से इंकार कर दिया कि मुकदमा धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा इस आधार पर वर्जित था कि इसे लिखित बयान में नहीं लिया गया था और यह एक नया विवाद था जिसे पहली बार द्वितीय अपील की स्टेज पर उठाया गया था। परिणामस्वरूप, उन्होंने वादी को अनुसूची ए में उल्लिखित संपत्तियों में से 136 एकड़ 45 सेंट के विभाजन और वितरण और भूत और भविष्यलक्षी मध्यवर्ती लाभ के लिए एक डिक्री प्रदान की। इस फैसले के खिलाफ, प्रतिवादी ने वर्तमान अपील दायर विशेष रूप से निवेदन किया कि मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जा सकता है।

अपीलकर्ता की ओर से, श्री सोमैया ने तर्क दिया कि यह सवाल कि क्या धारा 47 के संबंध में मुकदमा चलने योग्य है, विद्वान न्यायाधीश के समक्ष निष्कर्ष निकालने से पहले बहस की गई थी और इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए था गुण-दोष के आधार पर, और किसी भी स्थिति में, चूँकि यह कानून का एक शुद्ध प्रश्न था और मामले की जड़ तक जाता था, इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए था। उत्तरदाताओं की ओर से, श्री कृष्णास्वामी अयंगर ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि धारा 47 के आधार पर मुकदमे की संधारणीयता पर आपत्ति जवाब दावे में नहीं ली गई थी, विद्वान न्यायाधीश के पास यह विवेक था कि क्या उन्हें इस मुद्दे को उठाने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं। दूसरी अपील में पहली बार या नहीं, और हमें विशेष अपील में उस विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब जिस आधार पर मुकदमे का

फैसला सुनाया गया है, वह यह है कि मूल वाद संख्या 25/1927 को ठीक से समझा जाए तो यह केवल प्रदर्श ए के तहत बंधक अधिकारों की बिक्री का निर्देश देता है, न कि संपत्तियों की, लेकिन यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह बिंदु स्पष्ट रूप से वादी के सामने नहीं उभरता है। यह सच है कि इसमें ऐसे आरोप हैं जिन्हें उस प्रश्न को समझने के रूप में पढ़ा जा सकता है, लेकिन वे अस्पष्ट और अविनिर्दिष्ट हैं और इससे भी अधिक, इस विवाद पर अदालत में भी बहस नहीं की गई।

राजमुंदरी के अधीनस्थ न्यायाधीश या पूर्वी गोदावरी के जिला न्यायालय में और यह केवल दूसरी अपील में है कि इस प्रश्न पर पहली बार इस रूप में विचार किया गया है। यद्यपि हम यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि वाद में किये गये अभिवचन इस बिंदु को कवर करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, हमारी राय है कि वे इतने अस्पष्ट हैं कि यह संभव है कि अपीलकर्ता उनके वास्तविक आशय को भूल गया हो कि मुकदमा धारा 47 द्वारा वर्जित था और दलील देना भूल गया हो। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस बिंदु में तथ्यों की कोई नई जांच शामिल नहीं है। वास्तव में, जब मामला जिला न्यायाधीश के समक्ष था या उच्च न्यायालय द्वारा निष्कर्ष निकालने के लिए कहा गया था, तो दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने इसे इस बिंदु पर भी एक निर्णय के रूप में समझा और तर्क इस आधार पर आगे बढ़ा था कि यह कानून का एक शुद्ध प्रश्न जिसमें तथ्यों पर कोई और पूछताछ शामिल नहीं है। इसलिए हमने अपीलकर्ता को यह विवाद उठाने की अनुमति दी है।

अपीलकर्ता के लिए श्री सोमैया ने उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई जिला न्यायालय के निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी है कि डिक्री में केवल प्रदर्श ए के तहत अच्युतारामराजू के बंधक अधिकारों की बिक्री का निर्देश दिया है, लेकिन उनका तर्क है कि उस डिक्री के निष्पादन में बिक्री नहीं की जाएगी प्रदर्श ए के तहत केवल बंधक अधिकार, लेकिन स्वयं संपत्तियों का अत्यधिक निष्पादन था, जिसके खिलाफ निर्णित-

ऋणी निष्पादन अदालत में आवेदन द्वारा राहत प्राप्त करने का हकदार था और उसके संदर्भ में एक अलग मुकदमा धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वर्जित होगा। यह पूर्णतया स्थापित है कि जब किसी डिक्री के निष्पादन में बिक्री को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यह उसकी शर्तों के अनुसार उचित नहीं है, तो उस प्रश्न को, जब यह डिक्री के पक्षों के बीच उठता है, जो धारा 47, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत केवल एक आवेदन के माध्यम से उठाया जा सकता है और एक अलग मुकदमे में नहीं। जे. मैरेट, एमडी. के. शिराज़ी एंड संस में तथ्य यह थे कि निष्पादन अदालत द्वारा एक आदेश दिया गया था, जिसमें डिक्री की शर्तों के विपरीत, डिक्री-धारक को एक निश्चित निधि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। एक अलग मुकदमा निर्णित-ऋणी द्वारा इस आधार पर राशि की वसूली के लिए स्थापित किया गया था कि भुगतान डिक्री के अनुसार नहीं था। प्रिवी काउंसिल द्वारा यह माना गया था कि कार्रवाई धारा 47 के तहत वर्जित थी। सीधे तौर पर एक मामला वेंकट- चलपति अयेन बनाम पेरुमल अयेन है। इसमे मुकदमा एक बंधक को लागू करने के लिए था जो बंधककर्ता के स्वामित्व में रखी गई संपत्तियों और उसके द्वारा रखे गए बंधक अधिकारों दोनों से संबंधित था। उसमें पारित डिक्री के निष्पादन में, न केवल बंधक अधिकार बल्कि संपत्तियां भी बेची गईं। निर्णीत किया कि कर्ज़दार ने तब यह घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर किया कि जो बेचा गया था वह केवल बंधक अधिकार था और संपत्तियों पर कब्ज़ा वापस पाने के लिए था। यह माना गया कि इस तरह के मुकदमे को धारा 47 के तहत प्रतिबंधित किया गया था। बीरू महता बनाम श्यामा चरण खवास अब्दुल करीम बनाम इस्लामुन्निसा बीबी और लक्ष्मी नारायण बनाम लादुराम में दिए गए निर्णयों को भी देखें। हमारी राय में, स्थिति इतनी अच्छी तरह से स्थापित है कि बहस करना संभव नहीं है और तदनुसार यह माना जाना चाहिए कि वर्तमान मुकदमा धारा 47, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वर्जित है।

हालाँकि, इससे मामला समाप्त नहीं होता है। धारा 47, खंड (2) अधिनियमित करता है कि "अदालत, सीमा या क्षेत्राधिकार के संबंध में किसी भी आपत्ति के अधीन, इस धारा के तहत एक कार्यवाही को एक मुकदमे के रूप में या एक मुकदमे को एक कार्यवाही के रूप में मान सकती है..."। इस प्रावधान के तहत, इस न्यायालय के पास 7-8-1939 को प्रस्तुत वादपत्र को धारा 47 के तहत एक आवेदन के रूप में मानने की शक्ति है, बशर्ते कि उस तिथि पर दावा की गई राहत के लिए एक आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित न हो और आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि जिस अदालत में इसे दायर किया गया था वह डिक्री को निष्पादित करने के लिए सक्षम थी। परिसीमा के प्रश्न पर, प्रासंगिक तारीखें 14 और 15 अप्रैल, 1936 हैं, जब वादी की 81 एकड़ 86.50 सेंट बेची और 15 दिसंबर, 1936, जब अदालत के माध्यम से उस पर कब्जा कर लिया गया। शेष संपत्तियों के संबंध में, जिस तारीख को उन्हें बेचा गया था वह रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है, लेकिन वर्तमान उद्देश्य के लिए यह पर्याप्त है कि यह जिला मुंसिफ कोर्ट राजमुंदरी मूल वाद संख्या 268/1936 की स्थापना के बाद 14-12-1936 को हुआ था। अब, निर्धारण का मुद्दा यह है कि क्या वादपत्र को भारतीय सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 165 या अनुच्छेद 166 के तहत परिसीमा द्वारा वर्जित किया गया था, यदि इसे 7-8-1939 को प्रस्तुत निष्पादन आवेदन के रूप में माना जाता है, या क्या यह अनुच्छेद 181 के तहत समय में था।

अनुच्छेद 165 के तहत, अचल संपत्तियों से बेदखल किए गए और डिक्री-धारक या क्रेता के निष्पादन बिक्री के अधिकार पर विवाद करने वाले व्यक्ति द्वारा कब्जे में लेने के लिए एक आवेदन बेदखली के 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए। यदि यह वर्तमान कार्यवाही पर लागू होने वाला अनुच्छेद है, तो इसे निष्पादन आवेदन के रूप में माना गया वादपत्र समय से पहले दायर किया गया था। वचली रोहिणी बनाम

कोम्बी अलियासन में, मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने रत्नम अय्यर बनाम कृष्णा डॉस वाइटल और अब्दुल करीम बनाम श्री इस्लामुन्निसा बीबी में पहले व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से असहमति व्यक्त की है कि यह अनुच्छेद केवल आदेश 21, नियम 100, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निर्णित-ऋणियों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जे में बहाल होने के लिए आवेदनों पर लागू होता है और निर्णित-ऋणियों द्वारा इस आधार पर राहत का दावा करने वाले आवेदन कि उनके डिक्री के निष्पादन में संपत्तियाँ ग़लती से ली गई थीं, जो इसके द्वारा शासित नहीं होता है। रसूल बनाम अमीना और बहिर दास बनाम गिरीश चंद्र में इस दृष्टिकोण को मंजूरी दी गई और इसका पालन किया गया। हमारी राय है कि उपरोक्त निर्णयों में कानून सही ढंग से निर्धारित किया गया है, और उसके अनुसार, वर्तमान कार्यवाही अनुच्छेद 165 द्वारा वर्जित नहीं है। अनुच्छेद 166 के अनुसार डिक्री के निष्पादन में बिक्री को रद्द करने के लिए निर्णित-ऋणी द्वारा एक आवेदन, उस अनुच्छेद के तहत, बिक्री के 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना है। यदि वर्तमान कार्यवाही इस अनुच्छेद द्वारा शासित होती है, तो इसमें कोई प्रश्न नहीं हो सकता है कि वे सीमा से वर्जित हैं। लेकिन फिर, इस बात का प्रचुर अधिकार है कि अनुच्छेद 166 केवल तभी लागू होता है जब बिक्री ऐसी हो जो कानून के तहत उदाहरण के लिए, आदेश 21, नियम 89, 90 और 91 के तहत अलग रखा गया है, लेकिन बिक्री निष्क्रिय और शून्य होने पर इसका कोई उपयोग नहीं है। शेषगिरि राव बनाम श्रीनिवास राव 1919 आई०एल०आर० 43 मद्रास 313 में, अपीलकर्ता मुकदमे में एक पक्ष था, लेकिन डिक्री ने उसे दायित्व से मुक्त कर दिया था। डिक्री के निष्पादन में, संपत्तियों में उनका तीन-चौथाई हिस्सा 26-1-1910 को बेच दिया गया और डिक्री-धारक द्वारा खरीदा गया और 16-12-1910 को कब्जा उन्हें सौंप दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने 25-7-1911 को इस आधार पर बिक्री को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर किया कि यह डिक्री का उल्लंघन था और इसलिए अमान्य था। प्रतिवादी द्वारा यह

आपत्ति उठाए जाने पर कि मुकदमा धारा 47 के तहत वर्जित है, अदालत ने इसे बरकरार रखते हुए कहा कि वादपत्र को उस धारा के तहत एक आवेदन के रूप में माना जा सकता है यदि यह निष्पादन आवेदन के रूप में समय पर हो और निर्णय के लिए प्रश्न उठा कि क्या आवेदन भारतीय परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 166 या अनुच्छेद 181 द्वारा शासित था। यह माना गया कि चूंकि बिक्री अमान्य थी, इसलिए इसे कानून के तहत रद्द नहीं किया जाना था और इसलिए लागू अनुच्छेद 181 था न कि अनुच्छेद 166 कानून के इस कथन को मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया था। राजगोपालियर बनाम रेमंसजाचरियार 1928 आई०एल०आर० 47 मद्रास 288 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह का निर्णय मनमोथनाथ घोष बनाम लछमी देवी 1927 आई०एल०आर० 55 कलकत्ता 96 में दिया गया था, जिसमें न्यायाधिपति पेज द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि बिक्री को शून्य होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी और पारित किया जाने वाला आदेश "केवल सार रूप में" था। एक घोषणा कि बिक्री शून्य थी और इसका कोई प्रभाव नहीं था"। यह प्रश्न कि क्या एक निर्णित-ऋणी द्वारा इस आधार पर बिक्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन किया गया था कि अत्यधिक निष्पादन हुआ था और परिणामस्वरूप उसकी संपत्तियों की बिक्री शून्य थी अनुच्छेद 166 या अनुच्छेद 181 द्वारा शासित थी या अनुच्छेद 181 द्वारा सीधे विचार के लिए आया था। निरोडे काली रॉय बनाम हरेंद्र नाथ 1938 आई०एल०आर० 1 कलकत्ता 280 में यह मानते हुए कि आवेदन अनुच्छेद 181 द्वारा शासित था, न्यायाधिपति बी.के. मुखर्जी ने निर्धारित किया कि "अनुच्छेद 166 उन मामलों तक ही सीमित होना चाहिए जहां बिक्री केवल शून्यकरणीय है और शून्य नहीं है जब निष्पादन बिक्री शून्य है। यदि एक पक्ष धारा 47 के तहत शून्य घोषित करने के लिए या भविष्य की कठिनाईयों से बचने के लिए इसे अलग रखने के लिए आवेदन करता है तो उसका उचित अनुच्छेद 181 होगा, न कि भारतीय परिसीमा अधिनियम का

अनुच्छेद 166" शेषगिरि राव बनाम में निर्णय श्रीनिवास राव और राज-गोपालियर बनाम रामानुजचारिअर को फिर से मा वी ज्ञान बनाम माठंग थान बायु 126 में अपनाया गया, जिसमें यह माना गया कि यदि निष्पादन बिक्री शून्य थी, तो आवेदक के लिए इसे अपास्त कराना आवश्यक नहीं था और यदि ऐसी कोई प्रार्थना थी भी, तो वह आवेदन की वास्तविक प्रकृति को प्रभावित नहीं करेगी जो वास्तव में "प्रतिवादी को इस आधार पर संपत्ति परिदान करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए थी कि कोई वैध बिक्री नहीं हुई थी"। हम इन निर्णयों से सहमत हैं और मानते हैं कि जब निष्पादन में कोई बिक्री निष्क्रिय और शून्य होती है, तो निर्णित-ऋणी द्वारा इसे शून्य घोषित करने और उचित राहत के लिए एक आवेदन अनुच्छेद 181 द्वारा शासित होता है, न कि अनुच्छेद 166 द्वारा। अधीनस्थ न्यायालयों ने मूल वाद संख्या 25/1927 में यह माना है कि डिक्री को उचित रूप से केवल प्रदर्श ए के तहत अच्युतारामाराजू के बंधक अधिकारों की बिक्री के लिए अधिकृत किया गया था, न कि उन जमीनों को जो उस बंधक की विषय-वस्तु थीं, उत्तरदाता इसके हकदार थे। अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से गलत तरीके से बेची गई और अपीलकर्ता को सौंपी गई संपत्तियों का कब्जा दिलाने के लिए अदालत में आवेदन करें और ऐसा आवेदन अनुच्छेद 181 द्वारा शासित होगा। फिर, आगे सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 181 को लागू करते हुए, 7-8-1939 को प्रस्तुत वाद उस अनुच्छेद के तहत समय के भीतर था। जैसा कि पहले ही कहा गया है, 14 और 15 अप्रैल, 1936 को 81 एकड़ 581 सेंट बेचे गए थे। यदि सीमा का प्रारंभिक बिंदु बिक्री की तारीख है, तो आवेदन को वर्जित माना जाना चाहिए, जब तक कि वह अवधि जिसके दौरान मुकदमा लंबित था जिला मुंसिफ, राजमुंदरी की अदालत में, भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत अपवर्जित की जाती है। लेकिन यदि परिसीमन की गणना बेदखली की तारीख से की जानी है, तो आवेदन स्पष्ट रूप से समय पर होगा।

अनुच्छेद 166 के तहत, बिक्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन उसके 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

लेकिन यदि विचाराधीन बिक्री शून्य थी और इस कारण से अनुच्छेद 166 अनुपयुक्त हो जाता है, तो बिक्री की तारीख सीमा के शुरुआती बिंदु के रूप में गायब हो जानी चाहिए, क्योंकि इसका कानून में कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा तब तक नहीं है जब तक बिक्री के रंग में अभिनय करने वाला क्रेता उसके कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करता है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति बेची गई है वह वास्तव में व्यथित है और जो चीज उसे अनुच्छेद 181 के तहत आवेदन करने का अधिकार देती है वह ऐसा हस्तक्षेप या बेदखली है न कि बिक्री। जैसा कि मा वी ज्ञान बनाम माउंग थान बायु में देखा गया है, ऐसा आवेदन वास्तव में क्रेता द्वारा गलत तरीके से कब्जे में ली गई संपत्तियों की पुनर्वितरण के आदेश के लिए एक है। यदि यह सही स्थिति है, तो आवेदन करने का अधिकार बेदखली के कारण उत्पन्न होता है, न कि बिक्री के कारण, और सीमा के लिए प्रारंभिक बिंदु निपटान सत्र की तारीख होगी। ऐसा चेंगलराया बनाम कोल्लापुरी में निर्धारित किया गया था। वहाँ, मुकदमे के एक पक्ष की संपत्ति, जिसे डिक्री द्वारा निर्मुक्त कर दिया गया था, 8-1-1918 को उस डिक्री के निष्पादन में बेच दी गई थी और डिक्री-धारक द्वारा खरीदी गई थी। यह पाया गया कि उन्होंने 1919 में संपत्तियों पर वास्तविक कब्ज़ा कर लिया था। 23-11-1921 को निर्मुक्त प्रतिवादी के हित में प्रतिनिधियों ने इस आधार पर डिक्री-धारक क्रेता से संपत्तियों का कब्ज़ा वापस पाने के लिए कार्यवाही शुरू की। जिस बिक्री के तहत उसने दावा किया था वह शून्य थी। यह माना गया कि लागू सीमा का उचित अनुच्छेद 181 था और वह समय बिक्री की नहीं बल्कि वास्तविक बेदखली की तारीख से उस अनुच्छेद के तहत चलना शुरू हुआ और तदनुसार कार्यवाही समय पर की गई। हम इस निर्णय से सहमत हैं और यह मानते हैं कि मुकदमे में एक पक्ष द्वारा उन संपत्तियों पर कब्ज़ा वापस पाने के लिए एक आवेदन, जिनका परिदान

शून्य निष्पादन बिक्री के तहत किया गया था, अनुच्छेद 181 के तहत समय पर होगा, यदि ऐसा होता है उनको बेदखली के तीन साल के भीतर दायर किया गया था। इसलिए, 7-8-1939 को दायर वादपत्र को धारा 47 के तहत एक आवेदन के रूप में माने जाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, इस आधार पर कि यह परिसीमा द्वारा वर्जित है।

27. विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान मुकदमा ऐसी अदालत में दायर किया गया था जिसको मूल वाद संख्या 25/1927 में पारित डिक्री को निष्पादित करने का क्षेत्राधिकार था। वह काकीनाडा के अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित एक डिक्री थी, जबकि वर्तमान मुकदमा जिला न्यायालय, पूर्वी गोदावरी में दायर किया गया था, जिसके अधीन काकीनाडा के अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 38 में यह प्रावधान है कि किसी डिक्री को या तो उस अदालत द्वारा निष्पादित किया जा सकता है जिसने इसे पारित किया है या उस अदालत द्वारा जिसे इसे निष्पादन के लिए भेजा गया है। पूर्वी गोदावरी का जिला न्यायालय वह न्यायालय नहीं है जिसने मूल वाद संख्या 25/1927 में डिक्री पारित की थी और न कि वह अदालत जहां इसे निष्पादन के लिए भेजा गया था। लेकिन यह सामान्य आधार है कि जिला न्यायालय गोदावरी से पहले, संपत्तियों पर इसका अधिकार क्षेत्र था, जहां पूर्व में मुकदमा दायर किया गया था जो इस मुकदमे की विषय-वस्तु हैं। यह सत्य है कि यह अपने आप में पूर्वी गोदावरी के जिला न्यायालय को धारा 38 के प्रयोजन के लिए डिक्री पारित करने वाली अदालत बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि धारा 37 के तहत, यह केवल तभी होता है जब डिक्री पारित करने वाली अदालत का क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया हो। इसे निष्पादित करने के लिए कि निष्पादन आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर विषय-वस्तु पर जिस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, उसे डिक्री पारित करने वाला न्यायालय माना जा सकता है और यह स्थापित कानून है कि जिस अदालत ने

वास्तव में डिक्री पारित की है, वह इसे निष्पादित करने के अपने क्षेत्राधिकार को नहीं खोती है, क्योंकि विषय-वस्तु बाद में किसी अन्य अदालत के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती है। सीनी नादान बनाम मुथुस्वामी पिल्लई पूर्ण पीठ, मसरब खान बनाम देबनाथ माली और जगन्नाथ बनाम इच्छाराम देखें। लेकिन क्या इससे यह पता चलता है कि जिला न्यायालय, पूर्वी गोदावरी को मूल वाद सख्या 25/1927 में डिक्री के संबंध में निष्पादन आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र अधीनस्थ न्याायालय काकीनाड़ा काे नहीं है? कलकत्ता उच्च न्यायालय में निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है कि जब किसी डिक्री के विषय-वस्तु पर अधिकार क्षेत्र किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित किया जाता है, तो वह अदालत डिक्री के निष्पादन के लिए एक आवेदन पर विचार करने के लिए भी सक्षम होती है। लैचमैन बनाम मदन मोहनजहर बनाम कामिनी देवी और उदित नारायण बनाम मथुरा प्रसादलेकिन मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ मुथुकृष्ण अय्यर ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है और माना है कि डिक्री पारित करने वाली अदालत द्वारा स्थानांतरण के आदेश की अनुपस्थिति में, वह अदालत अकेले ही निष्पादन के लिए आवेदन पर विचार कर सकती है। न कि वह न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में विषय-वस्तु स्थानांतरित की गई है। यह दृष्टिकोण मसरब खान बनाम देबनाथ माली के निर्णय द्वारा समर्थित है। इस मामले में यह तय करना जरूरी नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा दृष्टिकोण सही है, क्योंकि यह मानते हुए भी कि रामियर बनाम मुथुकृष्ण अय्यर में व्यक्त राय सही है, वर्तमान मामला बालकृष्णय्या में निर्धारित सिद्धांत द्वारा शासित है। वी. लिंगा राव में यह माना गया था कि जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में डिक्री का विषय-वस्तु स्थानांतरित किया गया है, वह ऐसे स्थानांतरण के कारण उस पर अंतर्निहित क्षेत्राधिकार प्राप्त कर लेता है और यदि वह इसके संदर्भ में निष्पादन आवेदन पर विचार करता है, तो यह सबसे खराब स्थिति में यह क्षेत्राधिकार की एक अनियमित धारणा होगी, न कि इसकी पूर्ण अनुपस्थिति और

यदि इस पर आपत्ति जल्द से जल्द नहीं ली जाती है, तो इसे माफ कर दिया गया माना जाना चाहिए, और इसे बाद के किसी भी चरण में नहीं उठाया जा सकता है। कार्यवाही में यहाँ बिल्कुल यही स्थिति है। हमने माना है कि वादपत्र में किए गए अभिवचन अत्यधिक निष्पादन का सवाल उठाते हैं, और इसलिए अपीलकर्ता के लिए यह दलील देना खुला था कि मुकदमा धारा 47 द्वारा वर्जित था, और फिर, छूट का कोई सवाल ही नहीं हो सकता था। यह सत्य है कि हमने अपीलकर्ता को यह तर्क उठाने की अनुमति दी है कि वर्तमान मुकदमा धारा 47 द्वारा वर्जित है और इसका एक कारण यह है कि वाद पत्र में आरोप इतने अस्पष्ट हैं कि अपीलकर्ता चूक गया होगा कि उनका वास्तविक आधार क्या था, लेकिन यह उसे उस परिणाम से राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है जो उसके लिखित बयान में आपत्ति उठाने में विफलता पर होना चाहिए। हम बालकृष्णय्या बनाम लिंगा राव के फैसले से सहमत हैं और मानते हैं कि मूल वाद संख्या 25/1927 में जिला अदालत में डिक्री को निष्पादित करने के लिए एक आवेदन पर विचार करने वाली जिला अदालत में आपत्ति अभिव्यक्त की गई है और जवाब दावा में लिया गया विवरण अब अपीलकर्ता को उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार उत्तरदाताओं द्वारा 7-8-1939 को प्रस्तुत वाद-पत्र को धारा 47 के तहत निष्पादन आवेदन के रूप में मानने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, और न्याय के हित में, हम इसे इसी तरह व्यवहार करने का निर्देश देते हैं। लेकिन यह शर्तों पर होना चाहिए। हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सभी चरणों में उत्तरदाताओं की घोर लापरवाही ही सभी परेशानियों के लिए जिम्मेदार है। वे मुकदमे में उपस्थित नहीं हुए, और प्रदर्श ए के तहत अपने अधिकारों को सामने रखा। उन्होंने निष्पादन के चरण में हस्तक्षेप किया, लेकिन उनका मुख्य आधार यह था कि एक पक्षीय डिक्री धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी, एक याचिका जिसे अब अस्वीकार कर दिया गया है। इस मुकदमे में भी, उन्होंने उच्च न्यायालय में आने तक उस याचिका पर जोर नहीं दिया

जिस पर वे सफल हुए हैं। इन परिस्थितियों में, हमारा मानना है कि उन्हें इस तिथि तक मध्यवर्ती लाभ के सभी दावों से वंचित कर दिया जाना चाहिए।

परिणामस्वरूप, वादपत्र को एक निष्पादन आवेदन के रूप में मानते हुए, हम निर्देश देते हैं कि वादपत्र की अनुसूची ए में उल्लिखित संपत्तियों का विभाजन किया जाए और उत्तरदाताओं को कलावाचेरला गांव में 126 एकड़ 33 सेंट और नंदाराडा गांव में 10 एकड़ 12 सेंट का कब्जा दिया जाए। इस आदेश के परिपालन में की जाने वाली कार्यवाही। उत्तरदाता इस तिथि से उस तिथि तक उपरोक्त 136 एकड़ 45 सेंट की शुद्ध आय के अपने हिस्से के हकदार होंगे, जिस दिन उन्हें कब्जे से पृथक किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री संशाेधित की जाती है तथा अपील खारिज की जाती है। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रीति नायक आर जे एस द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।